International Journal of Sociology and Political Science
www.sociologyjournal.in
Online ISSN: 2664-7745, Print ISSN: 2664-7737
Received: 12-12-2021, Accepted: 28-12-2021, Published: 13-01-2022
Volume 4, Issue 1, 2022, Page No. 1-5

सरदार वल्लभभाई पटेलः भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन एवं राष्ट्रीय राजनीति में योगदान पर एक समग्र दृष्टि

गणेशा राम[1], सन्जू मीणा[2]

[1] सहायक आचार्य, राजनीति विज्ञान विभाग, श्री प्राज्ञ महाविद्यालय, बिजयनगर, अजमेर, राजस्थान, भारत
[2] शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर, राजस्थान, भारत

सारांश
31 अक्टूबर, 1875 गुजरात के काठियावाड़ जिले के एक छोटे से नगर नाडियाद में जन्मे सरदार वल्लभभाई पटेल ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने खेड़ा सत्याग्रह 1918, बारदोली सत्याग्रह 1928, अहमदाबाद महानगरपालिका अध्यक्ष, विदेशी वस्त्रों की होली जलाना और स्वदेशी को अपनाने जैसे आन्दोलन, कांग्रेस के 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता, सविधान सभा में विभिन्न समितियों की अध्यक्षता जैसे कई अहम मौकों पर भागीदारी निभाकर देश के स्वतंत्रता आन्दोलन में अपना योगदान दिया है। भारत के पहले गृहमंत्री और उप–प्रधानमंत्री के रूप मे सरदार पटेल ने भारतीय संघ में लगभग 562 से अधिक देशी रियासतों के एकीकरण में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायी। उस समय त्रावणकोर, हैदराबाद, जूनागढ़, भोपाल और कश्मीर जैसी कुछ रियासतें भारतीय संघ में शामिल होने के विरुद्ध थी। सरदार पटेल ने रियासतों के साथ आम सहमति बनाने के लिए अथक प्रयास किया लेकिन जहाँ भी आवश्यक हो वहाँ पर साम, दाम, दंड और भेद के तरीकों को अपनाने में संकोच नहीं किया। सरदार वल्लभभाई पटेल ने ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र के साथ–साथ रियासतों का एकीकरण किया और भारत के बाल्कनीकरण को भी रोका। भारतीय रियासतों के भारतीय संघ में एकीकरण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने और रियासतों को भारतीय संघ के साथ जुड़ने के लिए राजी करने हेतु इन्हें ''भारत के लौह पुरुष'' के रूप में जाना जाता है।

मूल शब्दः वल्लभभाई पटेल, लौह पुरुष, एकीकरण, स्वतंत्रता आन्दोलन, रियासतें, राष्ट्रीय राजनीति

प्रस्तावना
जनता की उन्नति उसके साहस, उसके चरित्र और उसकी बलिदान देने की शक्ति पर निर्भर करती है।[1]

सरदार वल्लभभाई पटेल
सरदार वल्लभभाई पटेल का जन्म एक किसान परिवार में 31 अक्टूबर, 1875 को गुजरात के काठियावाड़ जिले के छोटे से नगर नाडियाद में हुआ था, यहाँ पर उनका ननिहाल था। उनके पिता झबेरभाई व माता लाड़बा (लाड़बाई) खेड़ा जिले के बोरसद ताल्लुका के करमसद गाँव में खेती करते थे, उनके पास 10 एकड़ जमीन थी। उनके एक बेटी मणीबेन (जन्म–1903) तथा एक बेटा डाह्याभाई (जन्म–1905) थे। वे 'लेवा' नामक क्षत्रिय जाति के थे जो स्वयं को भगवान श्री राम के पुत्र लव का वंशज मानते हैं। लेवा जाति की पाटीदार शाखा से संबंधित होने के कारण सरदार वल्लभभाई के पूर्वज 'पटेल' कहलाए। [2]

सरदार वल्लभभाई पटेल की माता लाड़बाई, झबेरभाई की दूसरी पत्नी थी क्योंकि उनकी पहली पत्नी का देहांत होने के बाद अपनी आयु से 18 वर्ष छोटी लाड़बाई से उन्होंने विवाह किया। पहली पत्नी से उनके कोई संतान नहीं थी पर लाड़बाई ने उन्हें छः संतानें देकर निहाल कर दिया। सरदार पटेल पाँच भाई और उनके एक बहिन थी जो सबसे छोटी थी। सरदार पटेल अपने भाइयों में चौथे नम्बर के थे। सरदार पटेल की प्रारंभिक शिक्षा उनके गाँव करमसद में प्राथमिक स्कूल से शुरु हुई। उनकी पढ़ाई में रुचि होने के साथ–साथ उनमें संघर्ष करने की क्षमता तथा नेतृत्व का गुण भी था। सरदार पटेल ने 22 वर्ष की उम्र में मैट्रिक की परीक्षा पास की। सरदार वल्लभभाई पटेल की शादी झबेरबा से सन् 1893 में हुई लेकिन गौना वकील बनने के बाद गृहस्थी चलाने लायक होने पर हुआ। वे 1901 में जिला याचिकाकर्ता बन गये और गोधरा कोर्ट में प्रैक्टिस करने लगे। सरदार पटेल की पत्नी झवेरबा जिनका 1909 में बहुत कम उम्र मे निधन हो गया था उनको अदालत कक्ष में टेलीग्राम संदेश मिलने के बाद भी उन्होंने प्रतिवादी के हित में कोर्ट की कार्यवाही को आगे बढ़ाया। सरदार पटेल को वकालत का शौक था इसलिए उन्होंने आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए एक बड़े वकील के यहाँ सहायक के रूप में काम करना शुरु किया। इसी रूचि की बदौलत वे अगस्त 1910 में बैरिस्टरी की पढाई के लिए इंग्लैंड रवाना हुए तथा 36 साल की आयु में सरदार पटेल में बैरिस्टरशिप के लिए लंदन के 'मिडिल टेंपल इन' में दाखिला लिया तथा जून 1911 में उन्होंने बैरिस्टरी की परीक्षा पास की। अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया और 50 पाउंड का पुरस्कार प्राप्त किया। किसी भारतीय के इस तरह सफल होने का यह पहला और एकमात्र उदाहरण था जिन्होंने इतने कम समय में अच्छे अंकों से परीक्षा पास की थी। थोड़े समय बाद उन्होंने बैरिस्टर की उपाधि प्राप्त करने के पश्चात 1913 में वे स्वदेश लौटे।[3] उनकी 15 दिसंबर, 1950 को बंबई में मृत्यु हो गई।

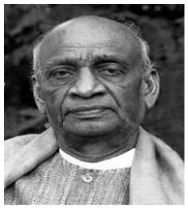

चित्र 1

स्वतंत्रता आन्दोलनों में भूमिका

सरदार पटेल द्वारा 13 फरवरी, 1913 को स्वदेश लौटने के बाद उन्होंने अहमदाबाद में अपनी वकालत शुरू की हालांकि उनके बड़े भाई विट्ठलभाई पटेल बंबई में वकालत करते थे लेकिन फिर भी उन्होंने अपना कार्यक्षेत्र अहमदाबाद चुना। इसके पीछे मुख्य वजह खेड़ावासियों को उनकी वकालत का लाभ मिले क्योंकि उनका गाँव करमसद खेड़ा जिले में स्थित होने तथा खेड़ा सैसनकोर्ट अहमदाबाद में ही स्थित होना था। सरदार पटेल उच्च कोटि के वकील थे उनकी वकालत और व्यक्तित्व का सभी सम्मान करते थे।[4] उन्होंने खेड़ा 1918, बोरसद 1924 और बारदोली 1928 जैसे प्रसिद्ध और सफल सत्याग्रहों में किसानों की अगुवाई की। उन्होंने कई स्वतंत्रता आन्दोलनों में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया।

खेड़ा सत्याग्रह 1918

महात्मा गांधी जी द्वारा 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद उनके द्वारा किसानों की समस्या को लेकर किया गया चम्पारण सत्याग्रह 1917 से प्रभावित होकर सरदार वल्लभभाई पटेल ने भी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन प्रवेश किया और खेड़ा सत्याग्रह में गांधीजी का पूर्ण साथ निभाया।

नाडियाद की सभा

खेड़ा सत्याग्रह के समापन का समारोह 29 जून, 1918 को मनाया गया। इस अवसर पर विशाल जुलूस निकाला गया जो बाद में जनसभा में परिवर्तित हो गया। सभा में गांधी जी का सम्मान करते हुए उन्हें एक प्रशस्ति–पत्र भैंट किया गया। उत्तर में गांधीजी ने संघर्ष की सफलता का श्रेय सरदार पटेल को देते हुए उनकी भूरि–भूरि प्रशंसा की। जिस तरह आरंभ में वल्लभभाई की राय गांधीजी के लिए बहुत अच्छी नहीं थी इसे स्वीकारते हुए गांधीजी ने कहा,"मैं मानता हूँ कि जब पहले–पहल मेरी मुलाकात वल्लभभाई से हुई तो मैंने सोचा कि अक्खड़ स्वभाव वाला यह व्यक्ति कौन होगा और यह क्या करेगा...! अगर वल्लभभाई मुझे न मिले हुए होते तो मैं जो काम कर पाया हूँ शायद ही कर पाता। इनका मुझे अच्छा अनुभव हुआ है।"[5] महात्मा गांधी जब जेल में थे तब 1923 में राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान को बनाये रखने के लिए उन्होंने नागपुर में झंडा सत्याग्रह का नेतृत्व किया।

म्युनिसिपैलिटी के अध्यक्ष

वर्ष 1924 में अहमदाबाद महानगरपालिका के अध्यक्ष चुने गए और अप्रैल 1928 तक कार्य किया। उन्होंने सारा समय नगर को स्वच्छ करने व सुंदर बनाने में लगा दिया। यह पटेल पर गांधीजी का ही प्रभाव था कि उन्होंने लोगों को सफाई के लिए प्रेरित करने के लिए खुद हाथ में झाड़ू पकड़कर सफाई की। उन्होंने नगरपालिका से आग्रह किया कि सभी स्कूलों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कर दिया जाए। सरकारी नियंत्रण का अर्थ था–शिक्षा भी सरकार के दृष्टिकोण से दी जाए जबकि पटेल राष्ट्रवादी शिक्षा के पक्षधर थे। पटेल के इसी विरोध के कारण अंग्रेजो की सरकार ने नगरपालिका को निलंबित कर दिया।[6]

राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान

ब्रिटिश सरकार से विरोध के चलते सरदार पटेल ने सामानान्तर शिक्षा के लिए राष्ट्रीय शिक्षा संस्थानों की स्थापना करने का निर्णय लिया। उनकी इस अपील का व्यापक प्रभाव पड़ा और थोड़े समय में ही इस कार्य के लिए सवा लाख रुपए जमा हो गये। इस राशि की सहायता से 43 राष्ट्रीय स्कूल खोलकर वल्लभभाई पटेल ने शिक्षा पर सरकारी नियंत्रण का करारा जवाब दिया। अंततः हार मानते हुए ब्रिटिश सरकार ने दो वर्षों बाद नगरपालिका को बहाल कर दिया। सरदार पटेल 1928 तक इसके अध्यक्ष बने रहे लेकिन इसके बाद बारदोली संघर्ष में पूरा समय देने के लिए उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया।[7]

विदेशी वस्त्रों की होली जलाना

अंग्रेजो का विरोध करने के लिए गांधीजी के आवाह्न पर विदेशी वस्तुओं की होली जलायी जाए, भविष्य में विदेशी वस्त्र न पहनने का व्रत ले और स्वदेशी अपनायें। इससे विदेशियों का मोटा मुनाफा बंद होगा व स्वदेशी भारतीय हथकरघा उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। 2 अक्टूबर, 1921 को गांधीजी के 53वें जन्मदिन पर अहमदाबाद में लोगों ने सरदार वल्लभभाई पटेल की नेतृत्व में एक विशाल जुलूस निकाला तथा उन्होंने विदेशी कपड़ों की होली जलायी।

बारदोली सत्याग्रह 1928

गांधीजी के द्वारा असहयोग आन्दोलन की शुरुआत करने का स्थान गुजरात में बारदोली चुनने के पीछे मुख्य कारण यह था कि यहाँ के निवासियों का शांत व दृढ़ निश्चयी होना तथा सरदार पटेल जैसे नेता का होना, जो इस आंदोलन को सुचारू रूप से चलाते। गांधीजी का संकेत पाकर सरदार पटेल ने तो पहले ही आन्दोलन आरंभ कर दिया था। उन्होंने कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन से पहले ही नाडियाद में हुए सम्मेलन में असहयोग आन्दोलन का प्रस्ताव पारित करा लिया था। सरदार वल्लभभाई पटेल ने किसानों की समस्याओं को दूर करने हेतु, सरकार की दमनकारी नीतियों का विरोध करने तथा आन्दोलन के प्रचार–प्रसार के लिए 'सत्याग्रह' नाम से एक पत्रिका भी निकाली।[8] इसी सत्याग्रह आन्दोलन के दौरान बारदोली की महिलाओं की तरफ से वल्लभभाई पटेल को 'सरदार' की उपाधि दी। 1918 में सफल खेड़ा सत्याग्रह, नागपुर ध्वज सत्याग्रह और बोरसद सत्याग्रह के बाद सरदार पटेल ने बारडोली में फिर एक बार किसानों की अगुवाई की। किसानों ने अंग्रेजो द्वारा लागू किए गए भूमि करों में मनमानी वृद्धि का विरोध किया। सरदार पटेल ने किसानों को संगठित किया और उनसे कहा कि वे कर का एक पैसा भी न दें। सरदार पटेल ने किसानों के साथ मिलकर ब्रिटिश सरकार को झुकने पर मजबूर किया। यह उनकी एक और शानदार जीत थी। वर्ष 1942 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने गांधीजी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आन्दोलन चलाया जिसके तहत सरदार पटेल के साथ कई अन्य स्वतंत्रता संग्राम के नेताओं को तीन वर्ष के लिए कारागार भेज दिया गया।

कांग्रेस के कराची अधिवेशन में सरदार पटेल की भूमिका

29 मार्च, 1931 में कराची में हुए कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभभाई पटेल ने की थी। इस अधिवेशन में गांधी–इरविन समझौते यानी दिल्ली समझौते को स्वीकृति प्रदान की गई। इसमें 'पूर्ण स्वराज्य'के लक्ष्य को फिर से दोहराया गया तथा भगतसिंह, राजगुरू व सुखदेव की वीरता तथा बलिदान की प्रशंसा की गयी। इस अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा दो प्रस्तावों को पास किया गया। जिनमें पहला प्रस्ताव – मूलभूत राजनीतिक अधिकारों (जैसे– अभिव्यक्ति एवं प्रेस की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, सभा या सम्मेलन आयोजित करने की स्वतंत्रता, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनावों की स्वतंत्रता, जाति, धर्म व लिंग से हटकर कानून के समक्ष समानता का अधिकार, सभी धर्मों के प्रति राज्य का तटस्थ भाव इत्यादि) तथा दूसरा प्रस्ताव – आर्थिक नीति से संबंधित (जैसे–किसानों को कर्ज से राहत, सूदखोरों पर नियंत्रण,

मजदूरों व किसानों को अपनी यूनियन बनाने की स्वतंत्रता, लगान व मालगुजारी में उचित कटौती, अलाभकारी जोतों को लगान से मुक्ति आदि) था।[9]

अप्रैल, 1931 के कांग्रेस के कराची अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने सरदार पटेल की अध्यक्षता में 'तिरंगे' को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया। ध्वज के रंगों को लेकर मतभेद व इसके विरोध को दूर करने को लेकर एक 7 सदस्य कमेटी का गठन किया। इस कमेटी के सुझावों को 8 अगस्त, 1931 को बंबई में स्वीकार करके इसके तीनों रंगों की मेहत्ता को प्रस्तुत किया गया।[10]

भारत के संविधान निर्माण में सरदार पटेल का योगदान

उन्होंने भारतीय संविधान सभा की विभिन्न समितियों का नेतृत्त्व किया[11]–

- मौलिक अधिकारों पर सलाहकार समिति।
- अल्पसंख्यकों और जनजातीय व बहिष्कृत क्षेत्रों पर सलाहकार समिति।
- प्रान्तीय संविधान समिति।

स्वतंत्रता के पश्चात सरदार पटेल की भूमिका

स्वतंत्र भारत के प्रथम उप–प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और सूचना एवं प्रसारण मंत्री नियुक्त हुए। यद्यपि लगभग सभी प्रान्तीय कांग्रेस समितियाँ पटेल को प्रधानमंत्री बनाने के पक्ष में थीं और वास्तविकता में सरदार वल्लभभाई पटेल ही प्रधानमंत्री पद के सच्चे हकदार व उपयुक्त उम्मीदवार थे क्योंकि सरदार पटेल महात्मा गांधीजी के बाद देश के सबसे लोकप्रिय व्यक्ति होने के साथ–साथ देशी रियासतों के एकीकरण का जो सबसे कठिन कार्य लगता था, उसे आसानी से करके दिखा दिया। सरदार पटेल पंडित नेहरु से हर तरह से बहुत आगे थे परन्तु महात्मा गांधीजी, पंडित जवाहरलाल नेहरु को प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे इसलिए सरदार वल्लभभाई पटेल ने गांधीजी की इच्छा का आदर करते हुए प्रधानमंत्री पद की दौड से अपने को दूर रखा और इसके लिए नेहरु का समर्थन किया। उन्हे उप–प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का कार्य सौंपा गया किन्तु इसके बाद भी नेहरू और पटेल के सम्बन्ध तनावपूर्ण ही रहे। इसके चलते कई अवसरों पर दोनो ने ही अपने पद का त्याग करने की धमकी दे दी थी। गृह मंत्री के रूप में उनकी पहली प्राथमिकता देसी रियासतों (राज्यों) को भारत में मिलाना था। इसको उन्होने बिना कोई खून बहाये सम्पादित कर दिखाया।

राष्ट्रीय राजनीति में योगदान

सरदार वल्लभभाई पटेल का राष्ट्रहित में यह सबसे महत्वपूर्ण और सर्वोच्च कोटि का कार्य था। उन्होंने भारत के लोगों से एकजुट (एक भारत) होकर एक साथ एक अग्रणी भारत (श्रेष्ठ भारत) बनाने का अनुरोध किया। भारत के पहले गृहमंत्री और उप–प्रधानमंत्री के रूप मे सरदार पटेल ने भारतीय संघ में लगभग 562 से अधिक रियासतों के एकीकरण में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायी। उस समय त्रावणकोर, हैदराबाद, जूनागढ़, भोपाल और कश्मीर जैसी कुछ रियासतें भारतीय संघ में शामिल होने के विरुद्ध थी। सरदार पटेल ने रियासतों के साथ आम सहमति बनाने के लिए अथक प्रयास किया लेकिन जहाँ भी आवश्यक हो वहाँ पर साम, दाम, दंड और भेद के तरीकों को अपनाने में संकोच नहीं किया। सरदार वल्लभभाई पटेल ने ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र के साथ–साथ रियासतों का एकीकरण किया और भारत के बाल्कनीकरण को भी रोका। भारतीय रियासतों के भारतीय संघ में एकीकरण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने और रियासतों को भारतीय संघ के साथ जुड़ने के लिए राजी करने हेतु इन्हें ''भारत के लौह पुरुष'' के रूप में जाना जाता है।[12]

देशी रियासतों का एकीकरण

स्वतंत्रता के पश्चात अखण्ड भारत की रचना करने में सरदार पटेल ने अहम भूमिका निभाई। भारत की स्वतंत्रता के तुरन्त बाद 562 से अधिक रियासतों के कई राजा–महाराजा और नवाब यह मानने लगे थे कि वे पूर्व की तरह अपने–अपने रजवाड़े के स्वतंत्र शासक बन जायेंगे। उनका तर्क था कि स्वतंत्र भारत की सरकार को उन्हें स्वतंत्र समझना चाहिए। ये तो सरदार पटेल की दूरदृष्टि, बुद्धिमत्ता और कूटनीति थी कि जिन्होंने उन राजाओं को आश्वस्त किया और वे अंततः भारत के गणराज्य में सम्मिलित होने के लिए सहमत हो गए।[13] इनका क्षेत्रफल भारत का 40 प्रतिशत था। सरदार पटेल ने आजादी के ठीक पूर्व (संक्रमण काल में) ही वीपी मेनन के साथ मिलकर कई देसी राज्यों को भारत में मिलाने के लिए कार्य आरम्भ कर दिया था। पटेल और मेनन ने देशी राजाओं को बहुत समझाया कि उन्हे स्वायत्तता देना सम्भव नहीं होगा। इसके परिणामस्वरूप तीन को छोडकर शेष सभी रजवाड़ों ने स्वेच्छा से भारत में विलय का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया केवल जम्मू एवं कश्मीर, जूनागढ तथा हैदराबाद रियासतों के राजाओं ने ऐसा करना नहीं स्वीकारा। जूनागढ सौराष्ट्र के पास एक छोटी रियासत थी और चारों ओर से भारतीय भूमि से घिरी थी। वह पाकिस्तान के समीप नहीं थी। वहाँ के नवाब ने 15 अगस्त, 1947 को पाकिस्तान में विलय की घोषणा कर दी। राज्य की सर्वाधिक जनता हिंदू थी और भारत में विलय चाहती थी। नवाब के विरुद्ध बहुत विरोध हुआ तो भारतीय सेना जूनागढ़ में प्रवेश कर गयी। नवाब भागकर पाकिस्तान चला गया और 9 नवम्बर, 1947 को जूनागढ भी भारत में मिल गया। फरवरी 1948 में वहाँ जनमत संग्रह कराया गया, जो भारत में विलय के पक्ष में रहा। हैदराबाद भारत की सबसे बड़ी रियासत थी, जो चारों ओर से भारतीय भूमि से घिरी थी। वहाँ के निजाम ने पाकिस्तान के प्रोत्साहन से स्वतंत्र राज्य का दावा किया और अपनी सेना बढ़ाने लगा। वह ढेर सारे हथियार आयात करता रहा। पटेल चिंतित हो उठे और उनके आदेश से अन्ततः भारतीय सेना 13 सितंबर, 1948 को (ऑपरेशन पोलो में सैन्य कार्रवाईं) हैदराबाद में प्रवेश कर गयी। तीन दिनों के बाद निजाम ने आत्मसमर्पण कर दिया और नवंबर 1948 में भारत में विलय का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। नेहरु ने कश्मीर को यह कहकर अपने पास रख लिया कि यह समस्या एक अन्तर्राष्ट्रीय समस्या है। कश्मीर समस्या को संयुक्त राष्ट्रसंघ में ले गये और अलगाववादी ताकतों के कारण कश्मीर की समस्या दिनोदिन बढ़ती गयी।[14] इस समस्या को हाल ही में 5 अगस्त, 2019 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदीजी और गृहमंत्री श्री अमित शाह जी के प्रयासों से जम्मू–कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाला अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35(ए) को समाप्त किया। जम्मू–कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया और सरदार पटेल का अखण्ड भारत बनाने का स्वप्न साकार हुआ। 31 अक्टूबर, 2019 को जम्मू–कश्मीर तथा लद्दाख के रूप में दो केन्द्र शासित प्रेदश अस्तित्व में आये। अब जम्मू–कश्मीर केन्द्र के अधीन रहेगा और भारत के सभी कानून वहाँ लागू होंगे। सरदार पटेलजी को कृतज्ञ राष्ट्र की यह सच्ची श्रद्धांजलि है।[15]

गांधी, पटेल और नेहरू

स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू व प्रथम उप–प्रधानमंत्री सरदार पटेल में आकाश–पाताल का अन्तर था। यद्यपि दोनों ने इंग्लैण्ड जाकर बैरिस्टरी की डिग्री प्राप्त की थी परन्तु सरदार पटेल वकालत में पंडित नेहरू से बहुत आगे थे तथा

उन्होंने सम्पूर्ण ब्रिटिश साम्राज्य के विद्यार्थियों में सर्वप्रथम स्थान प्राप्त किया था। नेहरू प्रायः सोचते रहते थे, सरदार पटेल उसे कर डालते थे। नेहरू शास्त्रों के ज्ञाता थे, पटेल शस्त्रों के पुजारी थे। पटेल ने भी ऊंची शिक्षा पाई थी परन्तु उनमें किंचित भी अहंकार नहीं था। वे स्वयं कहा करते थे, ''मैंने कला या विज्ञान के विशाल गगन में ऊंची उड़ानें नहीं भरीं। मेरा विकास कच्ची झोपड़ियों में गरीब किसान के खेतों की भूमि और शहरों के गंदे मकानों में हुआ है।'' पंडित नेहरू को गाँव की गंदगी, तथा जीवन से चिढ़ थी। पंडित नेहरू अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति के इच्छुक थे तथा समाजवादी प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। देश की स्वतंत्रता के पश्चात सरदार पटेल उप–प्रधानमंत्री के साथ प्रथम गृह, सूचना तथा रियासत विभाग के मंत्री भी थे। सरदार पटेल की महानतम देन 562 छोटी–बड़ी रियासतों का भारतीय संघ में विलीनीकरण करके भारतीय एकता का निर्माण करना। विश्व के इतिहास में एक भी व्यक्ति ऐसा न हुआ जिसने इतनी बड़ी संख्या में राज्यों का एकीकरण करने का साहस किया हो। 5 जुलाई, 1947 को एक रियासत विभाग की स्थापना की गई थी। एक बार उन्होंने सुना कि बस्तर की रियासत में कच्चे सोने का बड़ा भारी क्षेत्र है और इस भूमि को दीर्घकालिक पट्टे पर हैदराबाद की निजाम सरकार खरीदना चाहती है। उसी दिन वे परेशान हो उठे। उन्होंने अपना एक थैला उठाया व वी.पी. मेनन को साथ लिया और चल पड़े। वे उड़ीसा पहुंचे, वहां के 23 राजाओं से कहा, ''कुएं के मेढक मत बनो, महासागर में आ जाओ।'' उड़ीसा के लोगों की सदियों पुरानी इच्छा कुछ ही घंटों में पूरी हो गई, फिर नागपुर पहुँचे, यहाँ के 38 राजाओं से मिले। इन्हें 'सैल्यूट स्टेट' कहा जाता था, यानी जब कोई इनसे मिलने जाता तो तोप छोड़कर सलामी दी जाती थी। पटेल ने इन राज्यों की बादशाहत को आखिरी सलामी दी। इसी तरह वे काठियावाड़ पहुंचे। वहाँ 250 रियासतें थी जिनमें कुछ तो केवल 20–20 गाँव की रियासतें थी उन सबका एकीकरण किया। एक शाम बंबई पहुंचे तथा आसपास के राजाओं से बातचीत की और उनकी राजसत्ता अपने थैले में डालकर चल दिए। पटेल पंजाब गये, पटियाला का खजाना देखा तो खाली था। फरीदकोट के राजा ने कुछ आनाकानी की। सरदार पटेल ने फरीदकोट के नक्शे पर अपनी लाल पैंसिल घुमाते हुए केवल इतना पूछा कि ''क्या मर्जी है?'' राजा कांप उठा। आखिर 15 अगस्त 1947 तक केवल तीन रियासतों– जम्मू–कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद को छोड़कर इस लौह पुरुष शख्सियत ने सभी रियासतों को भारत में मिला दिया। इन तीन रियासतों में भी जूनागढ़ को 9 नवम्बर 1947 को मिला लिया गया तथा जूनागढ़ का नवाब पाकिस्तान भाग गया। 13 नवम्बर को सरदार पटेल ने सोमनाथ के भग्न मंदिर के पुनर्निर्माण का संकल्प लिया, जो पंडित नेहरू के तीव्र विरोध के पश्चात भी बना। 1948 में हैदराबाद भी केवल 4 दिन की पुलिस कार्रवाई द्वारा मिला लिया गया। इस प्रकार न कोई बम फूटा, न कोई रक्तरंजित क्रांति हुई, जैसा कि डराया जा रहा था। जहाँ तक जम्मू–कश्मीर रियासत का प्रश्न है इसे पंडित नेहरू ने स्वयं अपने अधिकार में लिया हुआ था, परन्तु यह सत्य है कि सरदार पटेल कश्मीर में जनमत संग्रह तथा कश्मीर के मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र संघ में ले जाने पर बेहद क्षुब्ध और दुःखी थे। निःसंदेह सरदार पटेल द्वारा इन 562 रियासतों का एकीकरण विश्व इतिहास का एक आश्चर्य था। भारत की यह रक्तहीन क्रांति थी। महात्मा गांधी ने सरदार पटेल को इन रियासतों के बारे में लिखा था, ''रियासतों की समस्या इतनी जटिल थी जिसे केवल तुम ही हल कर सकते थे।''यद्यपि विदेश विभाग पंडित नेहरू का कार्यक्षेत्र था, परन्तु कई बार उप–प्रधानमंत्री होने के नाते कैबिनेट की विदेश विभाग समिति में उनका जाना होता था। उनकी दूरदर्शिता का लाभ यदि उस समय लिया होता तो अनेक वर्तमान समस्याओं का जन्म न होता। 1950 में पंडित नेहरू को लिखे एक पत्र में पटेल ने चीन तथा उसकी तिब्बत के प्रति नीति से सावधान किया था और चीन का रवैया कपटपूर्ण तथा विश्वासघाती बतलाया था। अपने पत्र में चीन को अपना दुश्मन, उसके व्यवहार को अभद्रतापूर्ण और चीन के पत्रों की भाषा को किसी दोस्त की नहीं, भावी शत्रु की भाषा कहा था। उन्होंने यह भी लिखा था कि तिब्बत पर चीन का कब्जा नई समस्याओं को जन्म देगा। 1950 में नेपाल के संदर्भ में लिखे पत्रों से भी पंडित नेहरू सहमत न थे। 1950 में ही गोवा की स्वतंत्रता के संबंध में चली दो घंटे की कैबिनेट बैठक में लम्बी वार्ता सुनने के पश्चात सरदार पटेल ने केवल इतना कहा ''क्या हम गोवा जाएंगे, केवल दो घंटे की बात है।'' नेहरू इससे बड़े नाराज हुए थे। यदि पटेल की बात मानी गई होती तो 1961 तक गोवा की स्वतंत्रता की प्रतीक्षा न करनी पड़ती।[16]

अन्य महत्त्वपूर्ण योगदान

- गृहमंत्री के रूप में वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय नागरिक सेवाओं (आई.सी.एस.) का भारतीयकरण कर इन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवाएं (आई.ए.एस.) बनाया। अंग्रेजों की सेवा करने वालों में विश्वास भरकर उन्हें राजभक्ति से देशभक्ति की ओर मोड़ा। यदि सरदार पटेल कुछ वर्ष और जीवित रहते तो संभवतः नौकरशाही का पूर्ण कायाकल्प हो जाता। सरदार पटेल को आधुनिक अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना करने हेतु 'भारतीय सिविल सेवकों के संरक्षक संत' के रूप में भी जाना जाता है।[17]
- सरदार पटेल जहाँ पाकिस्तान की छद्म व चालाकी पूर्ण चालों से सतर्क थे वहीं देश के विघटनकारी तत्वों से भी सावधान करते थे। विशेषकर वे भारत में मुस्लिम लीग तथा कम्युनिस्टों की विभेदकारी सोच के प्रति सजग थे। अनेक विद्वानों का कथन है कि सरदार पटेल बिस्मार्क की तरह थे लेकिन लंदन के टाइम्स ने लिखा था ''बिस्मार्क की सफलताएँ पटेल के सामने महत्वहीन रह जाती हैं।" यदि पटेल के कहने पर चलते तो कश्मीर, चीन, तिब्बत व नेपाल के हालात आज जैसे न होते। पटेल सही मायनों में मनु के शासन की कल्पना थे। उनमें कौटिल्य की कूटनीतिज्ञता तथा महाराज शिवाजी की दूरदर्शिता थी। वे केवल सरदार ही नहीं बल्कि भारतीयों के हृदय के सरदार थे।
- उन्होंने शराब के सेवन, छुआछूत, जातिगत भेदभाव और महिला मुक्ति के लिए व्यापक पैमाने पर काम किया।

सरदार वल्लभभाई पटेल का स्मारक, सम्मान तथा उनसे संबंधित संस्थान

- **मुख्य स्मारकः स्टैच्यू ऑफ यूनिटी**

चित्र 2

इसकी ऊँचाई 240 मीटर है, जिसमें 58 मीटर का आधार है। मूर्ति की ऊँचाई 182 मीटर है, जो स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी से लगभग दोगुनी ऊँची है। 31 अक्टूबर, 2013 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की 137वीं जयन्ती के मौके पर गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुजरात के नर्मदा जिले में सरदार वल्लभ भाई पटेल के एक नए स्मारक का शिलान्यास किया। यहाँ लौह से निर्मित सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक विशाल प्रतिमा लगाने का निश्चय किया गया, अतः इस स्मारक का नाम 'एकता की मूर्ति' (स्टैच्यू ऑफ यूनिटी) रखा गया है। प्रस्तावित प्रतिमा को एक छोटे चट्टानी द्वीप 'साधू बेट' पर स्थापित किया गया है जो केवड़िया (गुजरात) में सरदार सरोवर बाँध के सामने नर्मदा नदी के बीच स्थित है। 2018 में तैयार इस प्रतिमा को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदीजी ने 31 अक्टूबर, 2018 को राष्ट्र को समर्पित किया। यह प्रतिमा 5 वर्षों में लगभग 3000 करोड़ रुपये की लागत से तैयार हुई है।[18]

- अहमदाबाद के हवाई अड्डे का नामकरण 'सरदार वल्लभभाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय विमानक्षेत्र' रखा गया है।
- वर्ष 2014 से सरदार वल्लभभाई पटेल के जन्मदिवस 31 अक्टूबर को 'राष्ट्रीय एकता दिवस' के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है।
- उन्हें मरणोपरान्त 1991 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'भारत रत्न' से सम्मानित किया गया।
- सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा एवं आपराधिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर
- सरदार पटेल विश्वविद्यालय, वल्लभ विद्यानगर, गुजरात
- सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय स्मारक, अहमदाबाद
- सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद
- सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
- सरदार वल्लभभाई पटेल स्टेडियम, अहमदाबाद
- सरदार वल्लभभाई पटेल पुलिस संग्रहालय, कोल्लम
- सरदार वल्लभभाई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सूरत
- सरदार पटेल प्रौद्योगिकी संस्थान, वलसाड
- सरदार पटेल प्रौद्योगिकी संस्थान, मुम्बई
- सरदार पटेल इंजीनियरिंग कॉलेज, मुम्बई
- सरदार पटेल विद्यालय, नई दिल्ली
- सरदार सरोवर बाँध, गुजरात।

निष्कर्ष

वल्लभभाई झबेरभाई पटेल (31 अक्टूबर, 1875–15 दिसंबर, 1950) जो 'सरदार पटेल' के नाम से लोकप्रिय होने के साथ एक महान भारतीय राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने भारत के पहले उप–प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और सूचना एवं प्रसारण मंत्री के रुप में कार्य किया। वे एक महान भारतीय अधिवक्ता और राजनेता थे। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता और भारतीय गणराज्य के संस्थापक पिता थे जिन्होंने देश को आजाद कराने के लिए स्वतंत्रता संघर्ष में अग्रणी भूमिका निभाई। उन्होंने भारत के एक स्वतंत्र और देशी रियासतों के एकीकरण द्वारा एकीकृत राष्ट्र निर्माण का महत्वपूर्ण कार्य किया। भारत में और अन्य जगहों पर उन्हें अक्सर हिंदी, उर्दू और फारसी में 'सरदार' कहा जाता था जिसका अर्थ है–'प्रमुख'। उन्होंने भारत के राजनीतिक एकीकरण और 1947 के भारत–पाकिस्तान युद्ध के दौरान गृहमंत्री के रूप में कार्य किया। उनके द्वारा लगभग 562 से अधिक रियासतों को मिलाकर एक स्वतंत्र भारत का जो साहसिक कार्य किया, जिसके कारण उन्हें "लौह पुरुष" के नाम से भी जाना जाता है।

सन्दर्भ सूची

1. कपूर सुशीलः 'लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल' प्रकाशक : विद्याविहार, दरियागंज नई दिल्ली, प्रथम संस्करण 2013, पृ.सं. 30
2. मेहरोत्रा एन. सी., कपूर रंजना : 'सरदार वल्लभभाई पटेल व्यक्ति एवं विचार,' प्रकाशक : आत्माराम एंड संस, कश्मीरी गेट दिल्ली, 2009, पृ.सं. 9
3. कपूर सुशील : 'लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल' प्रकाशक : विद्याविहार, दरियागंज नई दिल्ली, प्रथम संस्करण 2013 पृ.सं. 9–11
4. उपर्युक्त पृ.सं. 30–31
5. उपर्युक्त पृ.सं. 40
6. उपर्युक्त पृ.सं. 41
7. उपर्युक्त पृ.सं. 42
8. उपर्युक्त पृ.सं. 45
9. आलेख : 'अखण्ड भारत का सपना : सरदार वल्लभ भाई पटेल (1875–1950)' दृष्टि द विजन, 21 नवम्बर, 2019
10. चौपड़ा प्रभाः 'सरदार पटेल : भारत विभाजन', प्रकाशक : प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण 2010, पृ.सं. 74
11. लक्ष्मीकांत एम.: 'भारत की राजव्यवस्था' प्रकाशक : मैक्ग्रा हिल एज्युकेशन (इण्डिया) प्रा.लि छठवाँ संस्करण 2020, पृ.सं. 2.3
12. आलेख : 'सरदार वल्लभभाई पटेल' दृष्टि द विजन, 16 दिसम्बर, 2021
13. स्टेच्यू ऑफ की यूनिटी की वेबसाइटः एचटीटीपीएसः//डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू. स्टेच्यूऑफयूनिटी.इन से साभार
14. आलेखः 'भारत को एकजुट करने वाले सरदार पटेल' प्रभा साक्षी पत्रिका, 5 मार्च, 2016
15. नवभारत टाइम्सः "जम्मू–कश्मीर और लद्दाख अब दो अलग–अलग केंद्र शासित प्रदेश, नए बदलाव लागू" 31 अक्टूबर, 2019
16. आलेख : सरदार वल्लभभाई पटेल एक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और राजनीतिज्ञः गांधी, पटेल और नेहरू (विकिपीडिया)
17. स्टेच्यू ऑफ की यूनिटी की वेबसाइट : एचटीटीपीएसः//डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू. स्टेच्यूऑफयूनिटी.इन से साभार
18. अमर उजाला, अहमदाबाद : "पीएम मोदी ने दुनिया की सबसे ऊँची प्रतिमा 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' का किया अनावरण", 31 अक्टूबर, 2018